

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के सफल कार्यान्वयन हेतु मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में गठित "राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति "State Level Sanctioning and Monitoring Committee (SLSMC) की दिनांक 29.05.2018 को सम्पन्न 10^{वीं} बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति— संलग्न

कार्यवाही:—

सर्वप्रथम मुख्य सचिव-सह-अध्यक्ष के द्वारा बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया।

अपर मुख्य सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के विभिन्न घटकों अन्तर्गत तैयार किये गये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) / Conceptual Layout Plans, Annual Capacity Building Plan-2018 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गयी। योजनान्तर्गत तैयार DPR एवं Conceptual Layout Plans के आधार पर विभिन्न निकायों में आवास निर्माण हेतु समिति द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत निम्न वर्णित निर्णय लिए गए:—

1. गत बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि की गयी।
2. गत बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन पर समिति के द्वारा संतोष व्यक्त किया गया (परिशिष्ट क)
3. PMAY(U) के प्रथम घटक "स्व-स्थाने" स्लम पुनर्विकास अन्तर्गत निर्मित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों (DPRs) पर अनुमोदन दिया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्रथम घटक "स्व-स्थाने" स्लम पुनर्विकास अन्तर्गत कुल 07 शहरी स्थानीय निकायों में स्लमों के पुनर्विकास करने हेतु कुल 1728 आवासों के निर्माण के लिए निकायवार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPRs) तैयार किए गए हैं, जिनपर State Level Appraisal Committee (SLAC) का अनुमोदन प्राप्त है।

प्रस्तावित आवासीय परियोजनाओं के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर ली गई है। इस योजना अन्तर्गत आवासों का निर्माण लोक निजी भागीदारी (PPP) के अंतर्गत कराया जाएगा। उक्त हेतु विकासकर्ताओं/ निर्माणकर्ताओं का चयन खुली एवं पारदर्शी तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर निविदा आमंत्रित कर किया जाएगा।

जिस आवासीय परियोजना हेतु सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा के क्रम में Positive Premium का प्रस्ताव दिया जाएगा, उस स्थिति में निविदाकर्ता से प्राप्त धनराशि सरकार के खाते में जमा की जाएगी एवं जिस आवासीय परियोजना हेतु सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा के क्रम में Grant की मांग की जाएगी, उस स्थिति में निविदाकर्ता को Grant का भुगतान सरकार द्वारा उपलब्ध राज्य मद से किया जाएगा। इस घटक अंतर्गत परियोजनावार Positive Premium प्राप्त होने या सरकार द्वारा निविदाकर्ता को Grant दिये जाने की स्थिति सफल निविदा निष्पादन के पश्चात् स्पष्ट होगी।

योजना के प्रथम घटक अंतर्गत निकायवार प्राप्त प्रस्ताव निम्नवत् हैं :-

(Amount in Lakh)								
S. No.	Name of ULBs	No. of locations	Project Location	No. of DUs	Total Project cost	GoI Share @ Rs.1.0 Lakhs	Beneficiary Share @ Rs 0.50 Lakhs	Developer share
1	Pakur	1	Devpur	260	4192.99	260.00	130.00	3802.99
2	Jhumri Telaiya	1	Gumo	210	4361.31	210.00	105.00	4046.31
3	Sahibganj	2	Laltok & Rasulpur Dahla	100	2083.67	100.00	50.00	1933.67
4	Chaibasa	1	Salihatu	230	4677.47	230.00	115.00	4332.47
5	Chakradharpur	1	Harijanbasti	48	1137.29	48.00	24.00	1065.29
6	Chakulia	1	Hatchali and Sugribasa	180	3724.30	180.00	90.00	3454.30
7	Deoghar	2	Sundari & Hardalakund	700	11103.10	700.00	350.00	10053.10
Grand Total				1728	31280.12	1728.00	864.00	28688.12

भारत सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र (7A) पर वांछित सूचना के साथ-साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPRs) भारत सरकार को उपलब्ध कराये जाने पर समिति का अनुमोदन दिया गया।

4. PMAY(U) के तृतीय घटक "भागीदारी में किफायती आवास का निर्माण" अन्तर्गत निर्मित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों (DPRs)/Conceptual Layout Plans पर अनुमोदन दिया गया।

4.1 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तृतीय घटक "भागीदारी में किफायती आवास का निर्माण" अन्तर्गत राज्य के 11 शहरी स्थानीय निकायों में कुल 3574 आवासों के निर्माण हेतु निकायवार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPRs) तैयार किए गए हैं, जिसपर State Level Appraisal Committee (SLAC) का अनुमोदन प्राप्त है।

सभी 11 नगर निकायों से प्राप्त DPRs पर मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया गया है। प्रस्तावित आवासीय परियोजना के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर ली गई है। इस योजना अन्तर्गत आवासों का निर्माण EPC Mode अंतर्गत किया जाएगा। उक्त हेतु विकासकर्ताओं/निर्माणकर्ताओं का चयन खुली एवं पारदर्शी तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर निविदा आमंत्रित कर किया जाएगा।

प्रस्तावित परियोजनाओं अंतर्गत आवासों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता राशि 1.5 लाख रुपये प्रति आवास होगी एवं लाभुक अंशदान प्रति लाभुक रु० 0.50 लाख एवं शेष राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। निकायवार प्राप्त प्रस्ताव निम्नवत् हैं :-

(Rs. In Lakh)							
S. No.	Name of ULBs	Project Location	No. of DUs	Total Project cost	GoI Share @ Rs.1.5 Lakhs	Beneficiary Share @ Rs 0.50 Lakhs	State Share
1	Ranchi	Leprosy Colony	256	3089.20	384.00	128.00	2577.20
2	Jhumri Telaiya	Gumo	80	828.38	120.00	40.00	668.38
3	Giridih	Karharbari	200	1654.11	300.00	100.00	1254.11

4	Koderma	Plot No. 4093	90	829.62	135.00	45.00	649.62
5	Pakur	Devpur	380	2347.50	570.00	190.00	1587.50
6	Chakradharpur	Potka	1700	11836.37	2550.00	850.00	8436.37
7	Chaibasa	Salihatu	448	3110.09	672.00	224.00	2214.09
8	Jugsalai	Harijan Basti	96	719.34	144.00	48.00	527.34
9	Jamtara	Patharchapda	50	343.20	75.00	25.00	243.20
10	Mihijam	Leprosy Colony	64	599.20	96.00	32.00	471.20
11	Khunti	Jamwadag	210	2038.70	315.00	105.00	1618.70
Grand Total			3574	27395.71	5361.00	1787.00	20247.71

4.2 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तृतीय घटक “भागीदारी में किफायती आवास का निर्माण” अन्तर्गत राज्य के छः निकायों यथा राँची, धनबाद, जमशेदपुर, आदित्यपुर, मानगो एवं जुगसलाई में 40,000 EWS आवासों का निर्माण नई एवं उभरती तकनीक से कराया जाना प्रस्तावित है। उक्त आवासों का निर्माण PPP आधार पर Hybrid Annuity Model के तहत किया जाएगा। परियोजना अंतर्गत आवासों के निर्माण हेतु विस्तृत Drawings and Designs निविदा में चयनित सफल निविदाकर्ता द्वारा तैयार किये जाएँगे, जिसपर निर्माण पूर्व नियमानुकूल सक्षम प्राधिकारों से अनुमोदन प्राप्त किये जाएँगे। प्रस्तावित आवासीय परियोजनाओं के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर ली गई है।

उक्त के क्रम में राँची एवं आदित्यपुर नगर निगम अंतर्गत कुल 3689 आवासों के निर्माण हेतु परामर्शियों द्वारा Conceptual Layout Plans तैयार किये गए हैं, जिनपर State Level Appraisal Committee (SLAC) का अनुमोदन प्राप्त है।

प्रस्तावित परियोजनाओं अंतर्गत आवासों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता राशि 1.5 लाख रुपये प्रति आवास होगी एवं लाभुक अंशदान प्रति लाभुक रु० 0.50 लाख एवं शेष राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। प्रस्तावित आवासीय परियोजना विवरणी निम्नवत् है:—

Lakh)							(Rs. In
S. No.	Name of ULB	Project Location	No. of DUs	Total Project cost	GoI Share @ Rs.1.5 Lakhs	Beneficiary Share @ Rs 0.50 Lakhs	State Share
1.	Ranchi	Loadih Plot no. 758 & 759	427	4210.12	640.5	213.5	3356.12
		Sithio Plot No. 2209	157	1579.91	235.5	78.5	1265.91
		Lem 1107	185	1771.00	277.5	92.5	1401.00
		Lem 86	180	1763.97	270	90	1403.97
		Lem 2P	100	1023.31	150	50	823.31
		Hatia 1041	120	1190.15	180	60	950.15
2.	Adityapur	Kasidih	2520	17268.30	3780	1260	12228.30
Grand Total			3689	28806.76	5533.50	1844.50	21428.76

भारत सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र (7B) पर वांछित सूचना के साथ-साथ निकायवार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPRs)/Conceptual Layout Plans भारत सरकार को उपलब्ध कराये जाने पर समिति का अनुमोदन दिया गया।

१३

४

५

६

5. योजना के चतुर्थ घटक "लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण" हेतु निकायवार तैयार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों (DPRs) पर अनुमोदन दिया गया।

योजना के चतुर्थ घटक "लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण" हेतु राज्य के 16 शहरी स्थानीय निकायों में 5,535 आवासों के निर्माण हेतु निकायवार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) प्राप्त हुए हैं, जिसपर State Level Appraisal Committee (SLAC) का अनुमोदन प्राप्त है। प्रस्तावित 5,535 आवासों के निर्माण की कुल परियोजना राशि 20042.24 लाख रुपये है।

निकायवार लाभुकों की संख्या एवं अंशदान की विवरणी निम्नवत् है:-

Sl. No.	ULBs	No. of Beneficiaries ULB wise	Central Share @ Rs.1.5 Lakh	State Share @ Rs. 0.75 Lakh	Beneficiaries Contribution @ Rs. 1.371 Lakh	Total Cost of DUs	Unit Cost per DU
1.	Adityapur	142	213.00	106.50	194.68	514.18	3.621
2.	Bishrampur	1214	1821.00	910.50	1664.39	4395.89	
3.	Chakardharpur	116	174.00	87.00	159.04	420.04	
4.	Chas	390	585.00	292.50	534.69	1412.19	
5.	Dhanbad	1590	2385.00	1192.50	2179.89	5757.39	
6.	Dumka	113	169.50	84.75	154.92	409.17	
7.	Godda	264	396.00	198.00	361.94	955.94	
8.	Gumla	285	427.50	213.75	390.74	1031.99	
9.	Jamtara	192	288.00	144.00	263.23	695.23	
10.	Khunti	130	195.00	97.50	178.23	470.73	
11.	Latehar	189	283.50	141.75	259.12	684.37	
12.	Madhupur	190	285.00	142.50	260.49	687.99	
13.	Mango	81	121.50	60.75	111.05	293.30	
14.	Nagaruntari	276	414.00	207.00	378.40	999.40	
15.	Ranchi	343	514.50	257.25	470.25	1242.00	
16.	Seraikela	20	30.00	15.00	27.42	72.42	
Total		5535	8302.50	4151.25	7588.49	20042.24	3.621

अतः लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र (7C) पर वांछित सूचना के साथ-साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPRs) भारत सरकार (CSMC) को उपलब्ध कराए जाने पर समिति का अनुमोदन दिया गया।

6. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत योजना के चतुर्थ घटक "लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण" के अयोग्य लाभुकों की सूची को प्रत्यर्पित करने पर अनुमोदन दिया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत योजना के चतुर्थ घटक "लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण" हेतु अनुमोदित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों (DPRs) में जाँचोपरांत अयोग्य पाये गए लाभुकों की सूची भारत सरकार को प्रत्यर्पित करने हेतु समिति का अनुमोदन दिया गया। निकायवार प्रत्यर्पित सूची की विवरणी निम्नवत् है :-

Sl. No	ULB	Total Sanctioned DUs	No. of DUs Surrendered	Remaining DUs
1	Adityapur	1199	263	936
2	Bishrampur	2202	14	2188
3	Bundu	843	91	752

73

8

8

8

4	Chaibasa	1987	417	1570
5	Chakradharpur	1825	20	1805
6	Chakuliya	1698	20	1678
7	Chas	6676	1355	5321
8	Chatra	1057	20	1037
9	Chirkunda	567	11	556
10	Deoghar	8553	25	8528
11	Dhanbad	6433	129	6304
12	Dumka	871	20	851
13	Garhwa	2337	196	2141
14	Giridih	5452	94	5358
15	Hazaribag	3547	483	3064
16	Hussainabad	1152	4	1148
17	Jamtara	2180	54	2126
18	Jhumri Tiliya	3026	280	2746
19	Jugsalai	29	5	24
20	Khunti	1851	281	1570
21	Koderma	1100	289	811
22	Latehar	1450	0	1450
23	Madhupur	2167	154	2013
24	Majhiaon	1692	129	1563
25	Mango	683	62	621
26	Medininagar	2674	813	1861
27	Mihijam	397	200	197
28	Nagar Untari	2007	0	2007
29	Pakur	1919	49	1870
30	Phusro	246	23	223
31	Rajmahal	1093	12	1081
32	Ramgarh	1606	20	1586
33	Ranchi	15419	801	14618
34	Sahebganj	1670	447	1223
35	Seraikela	295	17	278
Total		87903	6798	81105

7. आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नई एवं उभरती तकनीक से **Demonstration Housing Project (DHP)** के निर्माण पर संशोधित **DHP Guidelines** के आलोक में समिति का अनुमोदन दिया गया।

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नई एवं उभरती तकनीक से राज्य में एक Demonstration Housing Project (DHP) का निर्माण Building Materials and Technology Promotion Council, भारत सरकार के माध्यम से कराए जाने का प्रस्ताव पूर्व में प्राप्त हुआ था, जिसके आलोक में झारखंडा, राँची में 63 आवासों का निर्माण DHP के अंतर्गत किए जाने के प्रस्ताव पर दिनांक: 03.10.2017 को संपन्न SLSMC की सातवीं बैठक में अनुमोदन प्राप्त करनेपरांत झारखंडा, राँची में DHP के निर्माण का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था।

भारत सरकार द्वारा DHP की मार्गदर्शिका में संशोधन कर संशोधित मार्गदर्शिका निर्गत की गई है, जिसके आलोक में DHP के निर्माण का संशोधन प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाना है।

3

A

3

3

उक्त के आलोक में डोरंडा, राँची में पूर्व चिन्हित 43.60 डिसमिल भूमि पर संशोधित मार्गदर्शिका के अनुसार DHP का निर्माण प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जाने पर समिति का अनुमोदन दिया गया।

8. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु तैयार वार्षिक क्षमता संवर्धन प्लान (Annual Capacity Building Plan-2018) पर अनुमोदन दिया गया।

8.1 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु Annual Capacity Building Plan तैयार किया गया है, जिसमें व्यय की जाने वाली राशि 4744.61 लाख रुपये प्रस्तावित है। वार्षिक क्षमता संवर्धन प्लान विवरणी निम्नवत् हैं :-

Sl. No.	Activity	State Share	Central Share	Total (In Lakh)
1	Establishment of SLTC	26.40	79.20	105.60
2	Establishment of CLTC	143.10	429.30	572.40
3	Trainings and workshops	0.00	21.40	21.40
4	Exposure Visits	0.00	6.00	6.00
5	Documentations/Research	0.00	5.00	5.00
6	IEC	0.00	128.29	128.29
7	TPQM	51.80	155.40	207.20
8	Social Audit	0.00	5.50	5.50
9	Geo-Tagging (100000 Dus@Rs200/- per DU)	0.00	200.00	200.00
	Total	221.30	1030.09	1251.39
10	A&O and Establishment cost @5 % Of (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	0.00	62.57	62.57
11	Project Management Consultancy of 240 project @ 1.5 % of the total project cost	857.66	2572.99	3430.65
	Total	1078.96	3665.65	4744.61

अतः वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु तैयार Annual Capacity Building Plan भारत सरकार को प्रेषित हेतु समिति का अनुमोदन दिया गया।

8.2 निकायों में योजना क्रियान्वयन हेतु निकाय स्तरीय तकनीकी कोषांग (CLTC) के पुनर्गठन के संबंध में प्रस्ताव पर समिति का अनुमोदन दिया गया।

Details of CLTC Specialists sanctioned/proposed posts under different ULBs					
Sl. No.	Name of the cities /Cluster	Population	No of posts at present		Proposed posts for FY-2018-19 after restructuring
			Sanctioned	Filled	
1	Ranchi	1147795	6	3	6
2	Bundu				2
3	Dhanbad	1314120	6	3	6
4	Chirkunda				2
5	Jamshedpur	1015394	6	3	6
6	Jugsalai				
7	Mango				
8	Chakuliya	892098	4	4	4
9	Chas (including Bokaro)				2
10	Phusro	114533	4	1	2
11	Giridih				2
12	Hazaribagh	197466	4	3	2

13	Chatra	49985			2
14	Ramgarh	123875			2
15	Deoghar	203123	4	2	2
16	Madhupur	55238			2
17	Saraikela	14252	4	1	2
18	Adityapur	174355			2
19	Dumka	47584			2
20	Basukinath	17123	4	0	2
21	Jamtara	29415			2
22	Mihijam	40463			2
23	Godda	48480	4	0	2
24	Pakur	45840			2
25	Lohardaga	57411	4	1	2
26	Gumla	51264			2
27	Simdega	42944	4	1	2
28	Khunti	36390			2
29	Medninagar	78396			2
30	Latehar	26981	4	1	2
31	Husainabad	29241			2
32	Bishrampur	42925			2
33	Garhwa	46059			2
34	Nagar utari	32725	4	2	2
35	Majiaon	18349			2
36	Chaibasa	69565	4	2	2
37	Chakardharpur	56531			2
38	kodarma	24633	4	2	2
39	jhumritilaiya	87867			2
40	Sahebganj	88214	4	2	2
41	Rajmahal	22514			2
42	Kapali	43256	0	0	2
43	Chatarpur	28450	0	0	2
44	Barharwa	24133	0	0	2
Total no. of cities = 44			74	31	96

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाई सम्पन्न की गई।

[Signature]

[Signature]

सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञापांक:— 07 / न0प्र0नि0 / PMAY (HFA) / 01 / 2015..... 1367 राँची, दिनांक: 29/5/2018

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के प्रधान आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/बैठक में उपस्थित सभी सदस्यगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]

(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

[Signature]

[Signature]

